

3. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आर्थिक रणनीतियाँ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई आर्थिक रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। इन रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादनता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, बाजार तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है।



Source: <https://vajiramandravi.com/>

3.1 कृषि उत्पादनता में वृद्धि

फसल उत्पादनता में सुधार किसानों की आय बढ़ाने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। अधिक उत्पादनता का अर्थ है कि समान भूमि क्षेत्र से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके, जिससे सीधे तौर पर किसानों की आय बढ़ती है।

इसे उन्नत बीजों के उपयोग, संश्लिष्ट उर्वरकों के प्रयोग, कुशल सिंचाई प्रणालियों और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर (स्ट्रीक कृषि), डिजिटल उपकरण और कृषि मशीनीकरण भी संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद करते हैं और फसल उत्पादन बढ़ाते हैं।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन भी उत्पादनता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृदा परीक्षण, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और जैविक पर्यायों का उपयोग मिट्टी को उर्वरता को बनाए रखने और फसल वृद्धि को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।

3.2 खेती की लागत में कमी

उत्पादन लागत को कम करना किसानों की आय बढ़ाने का एक और प्रभावी तरीका है। जब किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई जैसे इनपुट पर कम खर्च करते हैं, तो उनका शुद्ध लाभ बढ़ जाता है।

समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (INM), समेकित कीट प्रबंधन (IPM) और ड्रिप तथा स्प्रिंकलर जैसी कुशल सिंचाई विधियों को अपनाने से उत्पादन लागत कम होती है और उत्पादनता भी बनी रहती है।

कृषि मशीनों का उपयोग और कस्टम हायरिंग सेंटर श्रम लागत को कम करने और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा किसान समूहों के माध्यम से सामूहिक रूप से कृषि इनपुट खरीदने से भी खर्च कम किया जा सकता है।



Source: <https://www.instagram.com/>

2

INTRODUCTION

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद किसानों को अक्सर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कम उत्पादनता, बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव, कृषि इनपुट की उच्च लागत, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और आधुनिक तकनीकों तक सीमित पहुँच। ये चुनौतियाँ किसानों की आय को कम करती हैं और उनके आर्थिक जीवन में अस्थिरता पैदा करती हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने की अवधारणा का उद्देश्य कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियों से किसानों की आय बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। इसका अर्थ केवल फसल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि बेहतर संसाधन प्रबंधन, फसल विविधीकरण, बेहतर बाजार पहुँच और सहायक सरकारी नीतियों के माध्यम से लाभप्रदता बढ़ाना भी है।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें तकनीकी नवाचार, कुशल कृषि प्रणालियाँ, मजबूत विपणन प्रणाली, वित्तीय सहायता और नीतिगत सुधार शामिल हैं। उचित आर्थिक रणनीतियों और नीतियों को अपनाकर किसान अधिक उत्पादनता प्राप्त कर सकते हैं, उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं और अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार ने कृषि उत्पादनता बढ़ाने, अपूर्णत श्रृंखला को मजबूत करने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई पहलें शुरू की हैं। ये सभी उपाय मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

2. किसानों की आय दोगुनी करने का महत्व
किसानों की आय बढ़ाना ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब किसानों की आय बढ़ती है, तो वे कृषि में अधिक निवेश कर पाते हैं, आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं।

उच्च कृषि आय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में भी सहायक होती है और डेयरी, पौधे, मत्स्य पालन तथा कृषि-प्रसंस्करण जैसे सहायक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और समग्र कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है।

किसानों की आय दोगुनी करने से कृषि की स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) में भी सुधार होता है। बेहतर आर्थिक संसाधनों वाले किसान मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जल संरक्षण, उन्नत बीजों के उपयोग और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों में निवेश कर सकते हैं। ये सभी उपाय प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए उत्पादनता बढ़ाने में मदद करते हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिक आय किसानों को जलवायु परिवर्तन और बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनाती है। किसान फसल विविधीकरण, फसल बीमा योजनाओं और बेहतर कृषि प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। इस प्रकार, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सतत और समावेशी कृषि विकास को प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।



Source: <https://sageuniversity.edu.in/>

1

क्रमांक: COOP/2023/KOTA/201080/26/31

एग्रीकल्चर फ़ोरम फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ़ फार्मिंग सोसायटी

कोटा, राजस्थान



किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आर्थिक रणनीतियाँ और नीतियाँ

संकलन

डॉ. वीणा राठौर

संविदा शिक्षक, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कैलाश नगर अनुसूच उपग्रामिकी कॉलेज, मन्दनौर राजस्थान विद्यापीठ संविद्या कृषि विश्वविद्यालय, न्यासिगर, (म.प्र.)

3.3 फसल विधिवीकरण

फसल विधिवीकरण का अर्थ है एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न फसलों की खेती करना। यह पद्धति फसल विफलता, बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करती है।

किसान अपने कृषि तंत्र में कम, सब्जियाँ, मसाले, औषधीय पौधे और फूल जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को शामिल कर सकते हैं। ये फसलें पारंपरिक अनाज फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती हैं।

फसल विधिवीकरण में कृषि के साथ डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन जैसी सहायक गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है। ये अतिरिक्त आय स्रोत किसानों की कुल आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

3.4 मूल्य संवर्धन और कृषि-प्रसंस्करण

मूल्य संवर्धन का अर्थ है कृषि उत्पादों को संसाधित करके उनकी बाजार में कीमत बढ़ाना। कच्चे उत्पाद बेचने के बजाय किसान फसलों को आटा, तेल, अचार, जूस और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के रूप में तैयार कर सकते हैं। कृषि-प्रसंस्करण उद्योग नई आय के अवसर पैदा करते हैं और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करते हैं। प्रसंस्करण से कृषि उत्पादों की शelf लाइफ बढ़ती है और बाजार में उनकी मांग भी बढ़ती है। छोटे स्तर के ग्रामीण कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा देने से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

3.5 कृषि विपणन में सुधार

किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में प्रभावी विपणन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उचित बाजार तक पहुँच की कमी के कारण कई बार किसानों को अपने उत्पाद कम कीमत पर बेचने पड़ते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने में मदद करते हैं। पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली और प्रतिस्पर्धी बाजार प्रक्रिया उचित मूल्य सुनिश्चित करती है।

भंडारण सुविधाओं, कोल्ड चेन और परिवहन अवसंरचना का विकास कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है और किसानों को अनुकूल बाजार कीमत मिलने तक अपने उत्पाद सुरक्षित रखने में सहायता करता है।

4. सरकारी नीतियाँ और पहल

सरकार कृषि उत्पादकों को बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। ये नीतियाँ किसानों को आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी सहायता और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध कराने में मदद करती हैं।

4.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को कुछ निश्चित फसलों के लिए सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो। यह किसानों को बाजार में कीमतों में अचानक गिरावट से बचाता है और उन्हें आय की सुरक्षा प्रदान करता है।

MSP किसानों को अस्थिर उत्पादन में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनकी आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है।

4.2 फसल बीमा योजनाएँ

फसल बीमा योजनाएँ प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाली फसल हानि से जुड़े जोखिमों को प्रबंधित करने में किसानों की मदद करती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को वित्तीय मुआवजा प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी आय में होने वाली हानि कम होती है। बीमा कवरेज किसानों का कृषि में निवेश करने का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है।

4.3 प्रत्यक्ष आय सहायता

प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रम किसानों को कृषि खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ये योजनाएँ किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाती हैं और कृषि कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सहायता करती हैं। यह आर्थिक सहायता किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीदने में मदद करती है, जिससे अंततः उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है।

4.4 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का प्रोत्साहन

किसान उत्पादक संगठन (FPOs) किसानों को सामूहिक रूप से अपने उत्पादों का विपणन करने, कम लागत पर कृषि इनपुट खरीदने और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करते हैं। FPOs किसानों की सोदेबाजी की क्षमता को मजबूत करते हैं और बाजार तक उनकी पहुँच को बेहतर बनाते हैं। सामूहिक खेती और विपणन से लेन-देन की लागत कम होती है और लाभप्रदता बढ़ती है।

4.5 अवसंरचना विकास

ग्रामीण अवसंरचना जैसे सड़कें, सिंचाई प्रणाली, भंडारण सुविधाएँ और कोल्ड चेन का विकास कृषि की दक्षता और बाजार से जुड़ाव को काफी हद तक बेहतर बनाता है। बेहतर अवसंरचना से कटाई के बाद होने वाली हानि कम होती है और किसान अपने उत्पादों को दूर-दराज के बाजारों तक आसानी से पहुँचा सकते हैं, जहाँ उन्हें बेहतर कीमत प्राप्त हो सकती है।

5. किसानों की आय बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका

आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रिसिजन फार्मिंग (सटीक कृषि), ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मोबाइल आधारित सलाह सेवाएँ किसानों को फसल प्रबंधन से संबंधित बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं।

मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किसानों को जलवायु परिवर्तियों के अनुसार अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को बाजार कीमतों, कीट प्रकोप और उन्नत कृषि पद्धतियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं।

स्मार्ट सिंचाई प्रणालियाँ जल संरक्षण करने के साथ-साथ फसलों की उचित वृद्धि सुनिश्चित करती हैं। इन आधुनिक तकनीकों के उपयोग से संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग होता है और फसल उत्पादकता बढ़ती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

6. किसानों की आय दोगुनी करने में चुनौतियाँ

- ❖ यद्यपि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई रणनीतियाँ और नीतियाँ लागू की गई हैं, फिर भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।
- ❖ छोटे और खंडित भूमि जोत, ऋण सुविधाओं तक सीमित पहुँच, आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी तथा अपर्याप्त बाजार अवसंरचना किसानों की लाभप्रदता को प्रभावित करती रहती हैं।
- ❖ जलवायु परिवर्तन भी कृषि उत्पादन के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। अनिश्चित वर्षा, सूखा, बाढ़ और तापमान में उतार-चढ़ाव जैसी परिस्थितियाँ फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं।
- ❖ इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारी संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, कृषि विस्तार सेवाओं तथा स्वयं किसानों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है।

7. निष्कर्ष

किसानों की आय दोगुनी करना सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने और ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाना, खेती की लागत कम करना, फसल विधिवीकरण को बढ़ावा देना, बाजार तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना तथा मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना शामिल है।

प्रभावी नीतियों, आधुनिक तकनीकों और मजबूत संरचना ढाँचे के माध्यम से सरकारी सहयोग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही ग्रामीण अवसंरचना, किसान संगठनों और वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना किसानों की आर्थिक स्थिरता को काफी बढ़ा सकता है। आधुनिक कृषि पद्धतियों और संसाधनों के कुशल प्रबंधन को अपनाकर किसान अपनी उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी आय, जीवन स्तर और दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा।